



**Drishti IAS**



**करेंट अफेयर्स**

**राजस्थान**

**जुलाई**

**2024**

**(संग्रह)**

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009

Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501

Email: [help@groupdrishti.in](mailto:help@groupdrishti.in)

# अनुक्रम

<b>राजस्थान</b>	<b>3</b>
➤ मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना	3
➤ बस्टर्ड संरक्षण का अगला चरण	4
➤ कोटा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा	5
➤ राजस्थान में पर्यटन बोर्ड का गठन	5
➤ राजस्थान: सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य	6
➤ राजस्थान का लक्ष्य विद्युत और ऊर्जा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना	7
➤ राजस्थान बजट 2024	8
➤ सज्जनगढ़ जैविक उद्यान	8
➤ राजस्थान जनजातीय आंदोलन	9
➤ आदिवासियों की भील प्रदेश की मांग	9
➤ राजस्थान अल्पसंख्यक नागरिकता शिविर	10
➤ वैश्विक चुनौतियों के लिये जनजातीय समुदाय समाधान	10
➤ HUDCO और राजस्थान के बीच समझौता ज्ञापन	12
➤ राजस्थान के नए राज्यपाल	12

## राजस्थान

### मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

#### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पहले से ही लाभार्थी किसानों को 2,000 रुपए की अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की।

#### मुख्य बिंदु:

- इस योजना के तहत, 1,000 रुपए की पहली किस्त वितरित की गई है, इसके बाद 500 रुपए की दो किस्तें वितरित की गई हैं।
- ◆ योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये सहकारिता विभाग को नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया है।
- राजस्थान में लगभग 650 करोड़ रुपए की राशि 65 लाख से अधिक किसानों को इस पहली किस्त के हिस्से के रूप में सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त हुई।
- मुख्यमंत्री ने महिलाओं द्वारा संचालित 51 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को 3-3 लाख रुपए भी वितरित किये।
- ◆ महिलाओं द्वारा विशेष रूप से प्रबंधित इन समितियों का उद्देश्य नेतृत्व कौशल विकसित करना और महिलाओं को अपने विकास एवं कल्याण हेतु निर्णय लेने के लिये सशक्त बनाना है।

#### प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ( PM-KISAN )

- यह भारत सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- इसका क्रियान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
- इस योजना के तहत, केंद्र सरकार सभी भूमिधारक किसानों के बैंक खातों में तीन समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित करती है, चाहे उनकी भूमि कितनी भी बड़ी क्यों न हो।
- इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों ( SMF ) की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना है, ताकि प्रत्येक फसल चक्र के अंत में अनुमानित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य एवं उचित उपज सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न इनपुट खरीदे जा सकें। लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान की पूरी ज़िम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है।

#### सहकारी समिति ( Cooperative Society )

- सहकारी संस्थाएँ ज़मीनी/प्राथमिक स्तर पर लोगों द्वारा बाज़ार में सामूहिक सौदाकारी क्षमता का उपयोग करने के लिये बनाई गई संस्थाएँ हैं।
- ◆ इसका अर्थ विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएँ हो सकती हैं, जैसे कि एक साझा संसाधन का उपयोग करना या पूंजी साझा करना, एक साझा लाभ प्राप्त करना जो अन्यथा एक व्यक्तिगत उत्पादक के लिये प्राप्त करना मुश्किल होगा।
- कृषि में सहकारी डेयरियाँ, चीनी मिलें, कताई मिलें आदि उन किसानों के संयुक्त संसाधनों से बनाई जाती हैं जो अपनी उपज को संसाधित करना चाहते हैं।
- ◆ अमूल शायद भारत की सबसे प्रसिद्ध सहकारी समिति है।

## बस्टर्ड संरक्षण का अगला चरण

### चर्चा में क्यों ?

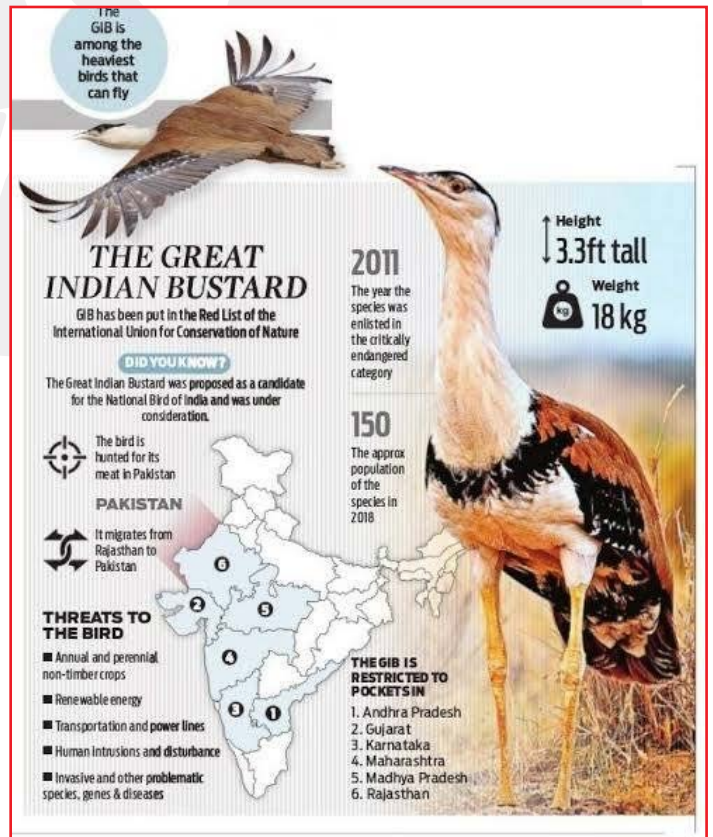
हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ( MoEFCC ) ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ( Great Indian Bustard- GIB ) तथा लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण के अगले चरण के लिये 56 करोड़ रुपए मंजूर किये हैं।

### मुख्य बिंदु:

- इस योजना में आवास विकास, स्व-स्थाने संरक्षण, संरक्षण प्रजनन केंद्र का निर्माण कार्य पूरा करना, बंदी-प्रजनित पक्षियों को मुक्त करना तथा अन्य गतिविधियाँ शामिल हैं।
- राष्ट्रीय CAMPA ( प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण ) ने भारतीय वन्यजीव संस्थान ( Wildlife Institute of India's- WII ) के प्रस्ताव की सिफारिश शासी निकाय को की थी।
- इस प्रजाति को पुनर्जीवित करने की योजना सर्वप्रथम वर्ष 2013 में राष्ट्रीय बस्टर्ड रिकवरी योजना के तहत शुरू की गई थी, जिसने बाद में 2016 में बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट को जन्म दिया।
- बाद में जुलाई 2018 में MoEFCC, राजस्थान वन विभाग और WII के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।
- तीनों पक्षों द्वारा संचालित परियोजना के हिस्से के रूप में दो GIB संरक्षण प्रजनन केंद्र और एक लेसर फ्लोरिकन केंद्र क्रमशः राजस्थान के सैम, रामदेवरा तथा सोरसन में कार्य कर रहे हैं।
- सैम और रामदेवरा की टीम ने इस प्रजाति की मूल आबादी ( Founder Population ) के पुनः वन्यीकरण हेतु वनों से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड/गोडावण के अंडों को एकत्र करके प्रजनन केंद्र में उनका कृत्रिम रूप से ऊष्मायन एवं उद्भवन ( Incubated and Hatched ) कर संवर्द्धन किया गया
- वर्तमान में वनों में लगभग 140 GIB और 1,000 से भी कम लेसर फ्लोरिकन शेष हैं।

### ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ( Ardeotis nigriceps ) राजस्थान का राजकीय पक्षी है और भारत का सबसे गंभीर रूप से संकटापन्न पक्षी माना जाता है।
- यह घास के मैदान की प्रमुख प्रजाति मानी जाती है, जो चरागाह पारिस्थितिकी का प्रतिनिधित्व करती है।
- ये अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में यह प्रजाति कम संख्या में पाई जाती है।
- सुरक्षा की स्थिति:
- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट: गंभीर रूप से संकटाग्रस्त
- वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ( CITES ): परिशिष्ट-1
- प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय ( CMS ): परिशिष्ट-I
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची-1



## लेसर फ्लोरिकन ( *Sypheotides indicus* )

- यह भारत में पाई जाने वाली तीन स्थानिक बस्टर्ड प्रजातियों में से एक है, अन्य दो प्रजातियाँ बंगाल फ्लोरिकन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं।
- स्थानीय भाषा में इस पक्षी को 'खरमोर' के नाम से जाना जाता है, जो मोर के मूल शब्द 'मोर' से निकला है।
- यह लुप्तप्राय पक्षी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाया जाता है।
- संरक्षण की स्थिति:
- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट: संकटग्रस्त
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची-1
- वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ( CITES ): परिशिष्ट II



## कोटा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान मंत्रिमंडल ने कोटा में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे और जयपुर में एक एयरोसिटी परियोजना के निर्माण को अनुमति दी।

### मुख्य बिंदु:

- अधिकारियों के अनुसार, राज्य के कई हवाई अड्डों पर कार्गो सेवाएँ शुरू की जाएँगी।
- राजस्थान का लक्ष्य विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। सौर ऊर्जा के लिये नई तकनीक विकसित की जाएगी।
- राज्य में किशनगढ़, भीलवाड़ा और झालावाड़ में तीन फ्लाईंग स्कूल खोले जाएँगे, जिससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।

## विमानन क्षेत्र ( Aviation Sector ) हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- डोमेस्टिक मटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल ( MRO ) सेवाओं के लिये वस्तु एवं सेवा कर ( GST ) की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई।
- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ( Emergency Credit Line Guarantee Scheme- ECLGS ) 3.0 के तहत लाभ नागरिक विमानन क्षेत्र तक बढ़ा दिये गए हैं।
- क्षेत्रीय संपर्क योजना ( Regional Connectivity Scheme- RCS )- उड़ान UDAN ( उड़े देश का आम नागरिक ) उड़ानों के संचालन ने PPP मार्ग के माध्यम द्वारा मौजूदा और नए हवाई अड्डों में निजी निवेश को बढ़ावा दिया।
- कुशल हवाई क्षेत्र प्रबंधन, छोटे मार्गों और कम ईंधन खपत के लिये भारतीय वायु सेना के साथ समवय में भारतीय हवाई क्षेत्र में मार्ग युक्तिकरण।
- क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने और नागरिकों को किफायती हवाई यात्रा उपलब्ध कराने के लिये टियर-II तथा टियर-III शहरों में असेवित एवं अल्पसेवित हवाई अड्डों तक हवाई संपर्क को बढ़ावा देने हेतु RCS-UDAN योजना शुरू की गई थी।
- 

## राजस्थान में पर्यटन बोर्ड का गठन

### चर्चा में क्यों ?

राजस्थान सरकार आर्थिक विकास में पर्यटन उद्योग की भूमिका बढ़ाने हेतु पर्यटन बोर्ड की स्थापना के लिये कदम उठा रही है।



**मुख्य बिंदु:**

- महामारी के बाद पर्यटन क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जो राज्य के **सकल घरेलू उत्पाद ( GDP )** में 14% का योगदान देता है।
- 1,200 से अधिक पर्यटन इकाइयाँ उद्योग की स्थिति के लाभों से लाभान्वित हो रही हैं।
- ◆ आगामी पर्यटन मार्ट में **अंतर्राष्ट्रीय टूर ऑपरेटरों** को शामिल करने की योजना का उद्देश्य विदेशी पर्यटकों की आमद को बढ़ाना है।

**भारत में पर्यटन से संबंधित पहल:**

- **स्वदेश दर्शन योजना:** इसे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत का लाभ उठाते हुए पूरे भारत में **थीम आधारित पर्यटन सर्किट** विकसित करने के लिये शुरू किया गया था।
- ◆ **बौद्ध सर्किट, तटीय सर्किट, डेज़र्ट सर्किट और इको सर्किट** जैसे सर्किटों में बेहतर बुनियादी ढाँचे तथा पर्यटक अनुभव।
- **प्रसाद योजना:** तीर्थ स्थलों के विकास और सौंदर्यीकरण पर केंद्रित है।
- **हृदय ( धरोहर शहर विकास और संवर्द्धन योजना ):** इसका उद्देश्य विरासत शहरों को संरक्षित तथा पुनर्जीवित करना है।
- **पर्यटन पर्व:** सांस्कृतिक कार्यक्रमों और गतिविधियों को शामिल करते हुए घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिये एक राष्ट्रव्यापी अभियान।
- **देखो अपनी देश पहल:** यह पहल भारत के विविध परिदृश्यों और सांस्कृतिक विरासत की खोज को बढ़ावा देकर घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करती है।
- **एक भारत श्रेष्ठ भारत:** यह राज्य युगों के माध्यम से सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देता है, आदान-प्रदान और सहयोग को प्रोत्साहित करता है तथा एकता व विविधता को बढ़ावा देता है, घरेलू पर्यटन एवं सांस्कृतिक प्रशंसा को बढ़ाता है।

**राजस्थान: सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य****चर्चा में क्यों ?**

राजस्थान अगले 10 वर्षों के लिये **सड़क सुरक्षा कार्ययोजना** अपनाने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। इस कार्ययोजना का उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाना है।

**मुख्य बिंदु**

- यह नीति आम जनता में सड़क सुरक्षा प्रावधानों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करेगी तथा सड़क सुरक्षा नियमों के अनुपालन के लिये व्यवहारिक परिवर्तन लाएगी।
- सूत्रों के अनुसार **विश्व बैंक** विभिन्न देशों में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करके कार्य योजना और सड़क सुरक्षा नीति तैयार करने में राज्य सरकार को सहायता प्रदान करेगा।
- ◆ कार्ययोजना तीन चरणों में क्रियान्वित की जाएगी। पहला चरण वर्ष 2025 से 2027 तक, दूसरा वर्ष 2027 से 2030 तक और तीसरा वर्ष 2030 से 2033 तक।
- इसमें गति सीमा, सुरक्षित दूरी, यातायात सिग्नल, सड़क अवरोधों का उपयोग, पैदल यात्री सुरक्षा, सीटबेल्ट, हेलमेट का उपयोग और वाहन बीमा के विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया जाएगा।

**सड़क सुरक्षा से संबंधित नई पहल**

- **विश्व:**
  - ◆ **सड़क सुरक्षा पर ब्राज़ीलिया घोषणा ( 2015 ):**  
ब्राज़ील में आयोजित सड़क सुरक्षा पर दूसरे वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन में घोषणा पर हस्ताक्षर किये गए। भारत घोषणा-पत्र का हस्ताक्षरकर्ता है।  
देशों ने **सतत् विकास लक्ष्य 3.6** यानी वर्ष 2030 तक सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली वैश्विक मौतों और दुर्घटनाओं की आधी संख्या करने की योजना बनाई है।

### ◆ सड़क सुरक्षा के लिये कार्रवाई का दशक 2021-2030:

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2030 तक कम-से-कम 50% सड़क यातायात मौतों और चोटों को रोकने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ "वैश्विक सड़क सुरक्षा में सुधार" संकल्प अपनाया।
- वैश्विक योजना सड़क सुरक्षा के लिये समग्र दृष्टिकोण के महत्त्व पर बल देते हुए **स्टॉकहोम घोषणा** के अनुरूप है।

### ◆ अंतर्राष्ट्रीय सड़क मूल्यांकन कार्यक्रम ( iRAP ):

- यह एक पंजीकृत चैरिटी है जो सुरक्षित सड़कों के माध्यम से लोगों की जान बचाने के लिये समर्पित है।

### ● भारत:

#### ◆ मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019:

- यह अधिनियम यातायात उल्लंघन, दोषपूर्ण वाहन, नाबलिकों द्वारा वाहन चलाने आदि के लिये दंड की मात्रा में वृद्धि करता है।
- यह अधिनियम **मोटर वाहन दुर्घटना हेतु निधि** प्रदान करता है जो भारत में कुछ विशेष प्रकार की दुर्घटनाओं पर सभी सड़क उपयोगकर्ताओं को अनिवार्य बीमा कवरेज प्रदान करता है।
- इसमें केंद्र सरकार द्वारा गठित **राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड** का भी प्रावधान है।

#### ◆ सड़क मार्ग द्वारा वाहन अधिनियम, 2007:

- यह अधिनियम सामान्य माल वाहकों के विनियमन से संबंधित प्रावधान करता है, उनकी देयता को सीमित करता है और उन्हें वितरित किये गए माल के मूल्य की घोषणा करता है ताकि ऐसे सामानों के नुकसान या क्षति के लिये उनकी देयता का निर्धारण किया जा सके, जो लापरवाही या आपराधिक कृत्यों के कारण स्वयं, उनके नौकरों या एजेंटों के कारण हुआ हो।

#### ◆ राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण ( भूमि और यातायात ) अधिनियम, 2000:

- यह अधिनियम राष्ट्रीय राजमार्गों के भीतर भूमि का नियंत्रण, रास्ते का अधिकार और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात का नियंत्रण करने संबंधी प्रावधान प्रदान करता है तथा साथ ही उन पर अनधिकृत कब्जे को हटाने का भी प्रावधान करता है।

#### ◆ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1998:

- ◆ यह अधिनियम राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिये एक प्राधिकरण के गठन तथा उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों से संबंधित प्रावधान प्रस्तुत करता है।

## राजस्थान का लक्ष्य विद्युत और ऊर्जा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना

### चर्चा में क्यों ?

राजस्थान सरकार ने **विद्युत और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर** बनने के लिये वित्त वर्ष 2025 के अंत तक 30 गीगावाट ( Gw ) सौर ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है।

### मुख्य बिंदु

- मार्च 2024 में राज्य सरकार और **नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ( NLC ) इंडिया** ने **बीकानेर** में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ 1,000 मेगावाट ( Mw ) सौर ऊर्जा संयंत्र तथा 125 मेगावाट लिग्नाइट-आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने हेतु एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- ◆ सरकार ने राज्य को ऊर्जा आत्मनिर्भरता में अग्रणी बनाने हेतु चार प्रमुख सौर परियोजनाओं के लिये भूमि को भी स्वीकृति दी।
- ◆ इन परियोजनाओं में **बीकानेर** में 2,450 मेगावाट के **तीन सौर पार्क** तथा फलौदी में 500 मेगावाट की एक परियोजना शामिल है।
- राज्य **PM कुसुम सौर पंप संयंत्र** को भी मजबूत कर रहा है, जिससे 50,000 से अधिक खेतों में सौर पंप स्थापित करने और 200 मेगावाट विद्युत उत्पादन में सहायता मिलेगी।
- ◆ यह पहल **नवीकरणीय ऊर्जा** स्रोतों को अपनाने को भी प्रोत्साहित करती है और सौर ऊर्जा चालित पंपों के कार्यान्वयन के माध्यम द्वारा राज्य में **कृषि क्षेत्र** को पुनर्जीवित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

## PM- कुसुम ( प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाभियान )

- PM- कुसुम योजना को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ( MNRE ) द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ-ग्रिड सौर पंपों की स्थापना तथा इन क्षेत्रों में ग्रिड पर निर्भरता कम करने के लिये शुरू किया गया था।
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ( CCEA ) ने फरवरी 2019 में वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू करने को मंजूरी दी थी।
- सरकार के 2020-21 के बजट में इस योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत 20 लाख किसानों को सौर पंप लगाने के लिये सहायता प्रदान की जाएगी; अन्य 15 लाख किसानों को उनके ग्रिड से जुड़े पंप सेटों को सौर ऊर्जा से चलाने के लिये सहायता दी जाएगी।
- ◆ इससे किसान अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित कर सकेंगे और उसे ग्रिड को बेच सकेंगे।

## राजस्थान बजट 2024

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये व्यापक बजट पेश किया है।

### मुख्य बिंदु

- जल जीवन मिशन परियोजनाओं के तहत 5,846 गाँवों को कवर करने वाली छह परियोजनाओं के लिये 20,370 करोड़ रुपए आवंटित किये जाएंगे।
- अमृत 2.0 परियोजनाओं के तहत अगले दो वर्षों में 185 शहरी बस्तियों में परियोजनाओं के लिये 5,180 करोड़ रुपए आवंटित किये जाएंगे।
- अजमेर में सेवा जलाशयों और पाइपलाइनों के निर्माण सहित लघु परियोजनाओं के लिये 187 करोड़ रुपए आवंटित किये जाएंगे।
- उत्पादन लक्ष्य बढ़कर 33,600 मेगावाट हो गया।
- ग्रामीण संपर्क में सुधार के लिये लोक परिवहन सेवा लागू की जाएगी।
- दो वर्षों के भीतर 208,000 घरों को कनेक्शन दिये जाएंगे; आदर्श सौर गाँव बनाने के लिये प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना; विद्युत् रिसाव (Electricity Leakage) को रोकने के लिये 2.5 मिलियन स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।
- प्रमुख शहरों में आधुनिक आश्रय स्थल और चार्जिंग स्टेशन; सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने के लिये 300 इलेक्ट्रिक बसें।
- बाईपास, राज्य राजमार्ग और बुनियादी ढाँचे में सुधार सहित नई सड़क परियोजनाओं के लिये 60,000 करोड़ रुपए; सड़क मरम्मत, रेलवे पुल, अंडरपास तथा सौंदर्यकरण परियोजनाओं के लिये 9,000 करोड़ रुपए आवंटित किये जाएंगे।
- नई औद्योगिक नीति 2024 और नई निर्यात संवर्धन नीति, 2024 का परिचय।
- कुल 2750 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाले नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा।
- शहरों में 71 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों, 131 विरासत अपशिष्ट प्रबंधन केंद्रों की स्थापना और अपशिष्ट संग्रह प्रबंधन में सुधार के लिये वाहन ट्रैकिंग प्रणाली तथा रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ( Radio-Frequency Identification- RFID ) प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिये 650 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।
- जयपुर वाल्ड सिटी हेरिटेज विकास योजना के लिये 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिसका उद्देश्य स्मारकों और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन विरासत स्थल को संरक्षित करना है।
- "एक ज़िला एक उत्पाद" पहल के तहत नई नीति लाई जाएगी। इसके लिये प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया जाएगा।
- ◆ स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिये "वोकल फॉर लोकल" योजना के तहत प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

## सज्जनगढ़ जैविक उद्यान

### चर्चा में क्यों ?

उदयपुर के सज्जनगढ़ जैविक उद्यान को पशु विनिमय पहल के तहत गुजरात के जूनागढ़ स्थित सक्करबाग प्राणी उद्यान से शेरों का एक जोड़ा मिलने की उम्मीद है।



**प्रमुख बिंदु:**

- 3.45 करोड़ रुपए के बजट वाली **लायन सफारी प्रोजेक्ट** का उद्देश्य वर्ष 2015 में स्थापित जैविक पार्क के आकर्षण को बढ़ाना है।
- ◆ 26 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस सफारी में शेरों के लिये एक होल्डिंग क्षेत्र और एक प्रदर्शन क्षेत्र दोनों शामिल होंगे, जिसमें आठ शेरों को रखने की क्षमता होगी।
- सक्करबाग चिड़ियाघर में सज्जनगढ़ जैविक उद्यान से **लोमड़ी, लकड़बग्घा, सियार, जंगली बिल्ली और चिंकारा** लाए जाएंगे।
- **केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण** ने वर्ष के अंत से पहले लायन सफारी शुरू करके उदयपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये फरवरी 2024 में शेरों के स्थानांतरण को मंजूरी दी।
- ◆ लायन सफारी के अलावा, जैविक पार्क अपनी सुविधाओं का विस्तार कर रहा है जिसमें **सरीसृप अनुभाग, रात्रिचर जानवरों का अनुभाग और तेंदुआ बचाव केंद्र** भी शामिल है।

**सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य**

- यह उदयपुर ( राजस्थान ) में स्थित है।
- यह वर्ष 1884 में निर्मित सज्जनगढ़ पैलेस ( जिसे मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है ) का एक हिस्सा है।
- ◆ महल का नाम मेवाड़ राजवंश के शासकों में से एक महाराणा सज्जन सिंह के नाम पर रखा गया है।
- यह चीतल, तेंदुआ, नीलगाय, सियार, जंगली सूअर, लकड़बग्घा और सांभर के लिये प्रसिद्ध है।

**राजस्थान जनजातीय आंदोलन****चर्चा में क्यों ?**

दक्षिणी राजस्थान के जनजाति बहुल क्षेत्रों में एक लोकप्रिय आंदोलन **स्वदेशी बीज किस्मों को संरक्षित** करने के लिये कार्य कर रहा है, जिनमें से अधिकांशतः विलुप्त होने के कगार पर हैं। यह प्रयास **फसल विविधता** को बढ़ावा दे रहा है और **जलवायु लचीलापन** बढ़ा रहा है।

**मुख्य बिंदु:**

- राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के ट्राइ-जंक्शन पर स्थित जनजातीय क्षेत्र में लगभग 1,000 गाँवों तथा बस्तियों से हजारों जनजातीय लोगों ने **बीज महोत्सवों** की श्रृंखला में भाग लिया।
- ◆ बीज महोत्सव में **पारंपरिक बीजों का प्रदर्शन** किया गया तथा उनके गुणों और महत्त्व पर **संवादात्मक सत्र आयोजित किये गए**।
- ◆ जनजातियों को कई पीढ़ियों से चली आ रही **कृषि प्रथाओं के माध्यम से जैवविविधता की अपनी समृद्ध विरासत की रक्षा** करने के लिये प्रोत्साहित किया गया।
- **कृषि क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों** के बढ़ते प्रभाव के बीच **स्वदेशी बीज जनजातीय समुदायों द्वारा संरक्षित एक महत्त्वपूर्ण विरासत है।**
- बाँसवाड़ा स्थित स्वैच्छिक समूह **वाग्धारा बीज उत्सव कार्यक्रमों का मुख्य आयोजक** था, जिसे अन्य **जनजाति अधिकार समूहों**, जैसे- **कृषि एवं आदिवासी स्वराज संगठन, ग्राम स्वराज समूह, सक्षम समूह और बाल स्वराज** द्वारा सुविधा प्रदान की गई थी।

**आदिवासियों की भील प्रदेश की मांग****चर्चा में क्यों ?**

हाल ही में राजस्थान के आदिवासी समुदाय ने 'भील प्रदेश' नामक एक नए राज्य के निर्माण की मांग की है।

**मुख्य बिंदु**

- आदिवासी समाज राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के 49 जिलों को मिलाकर एक नए राज्य के निर्माण की मांग कर रहा है।
- ◆ इसके अतिरिक्त, राजस्थान के पूर्व 33 जिलों में से 12 जिलों को नये राज्य में शामिल करने का अनुरोध किया गया है।

- **भील समुदाय** के सबसे बड़े समूह आदिवासी परिवार सहित 35 संगठनों ने एक विशाल रैली का आयोजन किया।
- ◆ बाँसवाड़ा के मानगढ़ धाम में आयोजित बैठक में मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से भी आदिवासी लोग एकत्रित हुए।

### भील समुदाय

- भील सबसे बड़े जनजातीय समूहों में से एक हैं, जो छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में रहते हैं।
- यह नाम 'बिल्लू' शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है धनुष।
- भील लोग उत्कृष्ट तीरंदाज माने जाते हैं तथा उन्हें स्थानीय भूगोल का भी गहरा ज्ञान है।
- परंपरागत रूप से गुरिल्ला युद्ध में माहिर, आज उनमें से ज्यादातर किसान और खेतिहर मजदूर हैं। वे कुशल मूर्तिकार भी हैं।
- भील महिलाएँ पारंपरिक साड़ी पहनती हैं जबकि पुरुष लंबी फ्रॉक और पायजामा पहनते हैं। महिलाएँ चाँदी, पीतल से बने भारी आभूषण पहनती हैं, साथ ही मोतियों की माला एवं चाँदी के सिक्के तथा झुमके भी पहनती हैं।

## राजस्थान अल्पसंख्यक नागरिकता शिविर

### चर्चा में क्यों ?

राजस्थान सरकार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के लिये विशेष शिविर आयोजित करने जा रही है।

### मुख्य बिंदु

- अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के नियम तथा प्रक्रियाएँ सरल कर दी गई हैं। अब जिला कलेक्टरों को नागरिकता प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है।
- सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2016 से 2024 तक राज्य में 2,329 लोगों को नागरिकता प्रदान की गई है।
- वर्तमान में कुल 1,566 आवेदन लंबित हैं। इनमें से 300 मामलों में आसूचना ब्यूरो (इंटेलिजेंस ब्यूरो) की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

### नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019

- नागरिकता ( संशोधन ) अधिनियम, 2019 का उद्देश्य नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करना है।
- नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment ACT- CAA) पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले छह गैर-मुस्लिम समुदायों ( हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी एवं ईसाई ) को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है।
- यह विधेयक छह समुदायों के सदस्यों को विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट अधिनियम, 1920 के तहत किसी भी आपराधिक मामले से छूट देता है।
- ◆ दोनों अधिनियमों में देश में अवैध रूप से प्रवेश करने तथा समाप्त हो चुके वीजा और परमिट पर यहाँ रहने के लिये दंड का प्रावधान किया गया है।

## वैश्विक चुनौतियों के लिये जनजातीय समुदाय समाधान

### चर्चा में क्यों ?

न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सतत विकास पर आयोजित उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम ( High-Level Political Forum- HLPF ) में वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिये राजस्थान के स्थानिक जनजातीय समुदायों के समाधान और नीतिगत भागीदारी पर प्रकाश डाला गया।

- राज्य के एक प्रतिनिधि ने चर्चा की कि कैसे जनजातीय समुदायों की पारंपरिक प्रथाओं ने उनकी समृद्ध प्राकृतिक विरासत के संरक्षण में योगदान दिया है।

**मुख्य बिंदु:**

- यह फोरम **संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ( Economic and Social Council- ECOSOC )** के तत्वावधान में आयोजित किया गया था।
- ◆ इसकी थीम थी '**Reinforcing the 2030 agenda and eradicating poverty in times of multiple crises: The effective delivery of sustainable, resilient and innovative solutions**' है जिसका अर्थ '2030 के एजेंडे को सुदृढ़ करना और विभिन्न संकटों के समय गरीबी उन्मूलन: सतत्, लचीले और नवीन समाधानों का प्रभावी वितरण'।
- मंच पर अपनाए गए मंत्रिस्तरीय घोषणा-पत्र में **सतत् विकास लक्ष्यों ( Sustainable Development Goals- SDG )** को प्राप्त करने के लिये नए सिरे से प्रोत्साहन देने का आह्वान किया गया।
- ◆ ECOSOC की अध्यक्ष पाउला नावेज़ के अनुसार, मंत्रिस्तरीय घोषणा ने **सतत् विकास के लिये 2030 एजेंडा** को लागू करने की तात्कालिकता पर जोर दिया है।
- मंच पर विशेषज्ञों ने **जैवविविधता और पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान के लिये स्वदेशी समुदायों को मान्यता देने के महत्त्व** पर जोर दिया।
- ◆ उन्होंने रणनीति निर्माण में **इन समुदायों की वैश्विक भागीदारी** की वकालत की तथा इस बात पर प्रकाश डाला कि उनकी पारंपरिक प्रथाएँ सतत् विकास के लिये आवश्यक अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं।
- **प्राकृतिक और समुदाय-केंद्रित दृष्टिकोणों के प्रति विश्वास पर आधारित स्थानिक प्रथाएँ स्थिरता तथा लचीलेपन को बढ़ावा दे सकती हैं**, जो संकट के बीच वर्ष 2030 के एजेंडे को सुदृढ़ करने के लिये आवश्यक हैं।
- **स्वराज के सिद्धांतों ( संप्रभुता )** से प्रेरित होकर, जनजातीय समुदायों की **जीवनशैली और सांस्कृतिक मूल्यों** ने **आत्मनिर्भरता को बढ़ावा** दिया है, बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम की है तथा **कृषि पद्धतियों में सुधार किया है**, जिससे उनके परिवारों के लिये भोजन, पोषण और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।
- ◆ फोरम में **जिन जनजातियों की सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रकाश डाला गया, उनमें स्थानीय बीजों का उत्पादन, स्रोत पर जल संरक्षण, कृषि में पशुओं का उपयोग, मिश्रित फसलों के माध्यम से मृदा अपरदन को रोकना तथा पोषण सुरक्षा के लिये बिना कृषि वाले खाद्यान्न का उपयोग शामिल थे।**
- ◆ इन प्रथाओं ने **जनजातीय समुदायों को बाज़ार पर अपनी निर्भरता कम करने और वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी सहित कठिन दौर के दौरान जीवित रहने में मदद की है।**
- **जनजातीय समुदायों की पारंपरिक प्रथाएँ** न केवल उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेंगी, उन्हें **सतत् और लचीले समाधान प्रदान करेंगी**, बल्कि **गरीबी, असमानता और सुभेद्यता के मुद्दों को हल करने में भी मदद करेंगी**, ताकि सतत् विकास लक्ष्य (SDG) के लिये वर्ष 2030 के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके।

**संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ( Economic and Social Council- ECOSOC )**

- वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित यह निकाय आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर **समन्वय, नीति समीक्षा, नीति संवाद तथा सिफारिशों** के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिये **प्रमुख निकाय** है।
- इसके **54 सदस्य हैं**, जिन्हें **संयुक्त राष्ट्र महासभा** द्वारा तीन वर्ष के कार्यकाल के लिये **निर्वाचित** किया जाता है।
- यह **सतत् विकास** पर विचार करने, संवाद और रचनात्मक सोच के लिये संयुक्त राष्ट्र का **केंद्रीय मंच** है।
- ◆ प्रतिवर्ष ECOSOC सतत् विकास के लिये वैश्विक महत्त्व की **वार्षिक थीम** के इर्द-गिर्द अपनी कार्य संरचना बनाता है।
- यह **संयुक्त राष्ट्र की 14 विशिष्ट एजेंसियों**, दस कार्यात्मक आयोगों और पाँच क्षेत्रीय आयोगों के **कार्यों का समन्वय करता है**, नौ संयुक्त राष्ट्र निधियों तथा कार्यक्रमों से रिपोर्ट प्राप्त करता है एवं संयुक्त राष्ट्र प्रणाली व सदस्य राज्यों के लिये नीतिगत सिफारिशें जारी करता है।

## HUDCO और राजस्थान के बीच समझौता ज्ञापन

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में आवास एवं शहरी विकास निगम ( हुडको-HUDCO ) लिमिटेड ने आवास और शहरी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता के संबंध में राजस्थान सरकार के साथ एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन ( MoU ) पर हस्ताक्षर किये।

### मुख्य बिंदु

- यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों के बीच एक प्रारंभिक समझौता है, जिसके तहत राजस्थान में आवास और शहरी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये अगले पाँच वर्षों में 1,00,000 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों एवं नियमों के अधीन होगी।

### आवास एवं शहरी विकास निगम ( हुडको )

- आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हुडको, “Profitability with Social Justice अर्थात् सामाजिक न्याय के साथ लाभप्रदता” के आदर्श वाक्य के साथ राष्ट्र के लिये परिसंपत्तियों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है।
- इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ( EWS ) और निम्न आय समूहों ( LIG ) की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर दिया गया है।

## राजस्थान के नए राज्यपाल

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ( RSS ) के वरिष्ठ नेता हरिभाऊ किसनराव बागड़े को राजस्थान का नया राज्यपाल नियुक्त किया है।

### मुख्य बिंदु

- राज्यपाल की नियुक्ति, उसकी शक्तियाँ और उसके पद से संबंधित अन्य सभी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 में शामिल हैं।
- राज्यपाल की भूमिका भारत के राष्ट्रपति के समान ही है। राज्यपाल राष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है, किंतु उसके कार्य राज्य विशिष्ट होते हैं।
  - राज्यपाल राज्य के कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करता है और उसका कार्य भारत के राष्ट्रपति के समान ही रहता है।
  - भारतीय संविधान के तहत इसमें शासन तंत्र केंद्र सरकार के समान ही होता है।
- संविधान के मुताबिक, राज्य का राज्यपाल दोहरी भूमिका अदा करता है।
  - वह राज्य की मंत्रिपरिषद ( CoM ) की सलाह मानने को बाध्य होता है और साथ ही राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है।
  - इसके अतिरिक्त वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है।

### राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ( RSS )

#### परिचय

- ◆ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) एक हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1925 में नागपुर में डॉ. के.बी. हेडगेवार ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान कथित खतरों से रक्षा एवं इसके प्रत्युत्तर के रूप में हिंदू संस्कृति और भारतीय नागरिक समाज के मूल्यों को बनाए रखने के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिये की थी
- ◆ इसका उद्देश्य हिंदुत्व के विचार को बढ़ावा देना है।

- स्वतंत्रता-पूर्व चरण:

- ◆ इस संगठन ने हिंदुओं के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक समन्वय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने सामुदायिक सेवा, शिक्षा एवं हिंदू मूल्यों के प्रचार पर ध्यान केंद्रित किया।

- स्वतंत्रता-उपरांत:

- ◆ वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, RSS जाँच के घेरे (वर्ष 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या के बाद) में आ गया। इसके बाद इस संगठन पर कुछ समय के लिये प्रतिबंध लगाया गया था लेकिन बाद में इस प्रतिबंध को हटा दिया गया।

- विचारधारा:

- ◆ विनायक दामोदर सावरकर द्वारा व्यक्त की गई RSS की केंद्रीय विचारधारा इस विचार को बढ़ावा देती है कि भारत, मूल रूप से एक हिंदू राष्ट्र है।
  - RSS भारतीय संस्कृति और विरासत के महत्त्व पर बल देता है, जिसका उद्देश्य भारतीयों को एक समान राष्ट्रीय पहचान के तहत संगठित करना है।
  - यह संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आपदा राहत सहित विभिन्न सामाजिक सेवा गतिविधियों में संलग्न है, जो अपने सदस्यों के बीच “सेवा भाव” के विचार को बढ़ावा देता है।

